वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
मंत्रिमंडल के लिए दिसम्बर, 2023 माह हेतु डीपीई का मासिक उपलब्धियां
****

1. कैपेक्स लक्ष्य:

दिसम्बर, 2023 तक चुनिंदा सीपीएसईज़ (100 करोड़ रुपये और उससे अधिक के वार्षिक कैपेक्स लक्ष्य वाले) और अन्य सरकारी संगठनों के संबंध में वार्षिक कैपेक्स लक्ष्यों और इसकी उपलब्धि से संबंधित जानकारी दिनांक 05 जनवरी, 2024 को प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत की गई थी। ₹7.33 लाख करोड़ (बजट अनुमान) के अनुमानित व्यय की तुलना में, उपलब्धि ₹5.51 लाख करोड़ (लगभग) अर्थात् दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक लगभग 75.09% थी। दिसम्बर, 2022 तक की समान अवधि में अनुमानित कैपेक्स ₹6.62 लाख करोड़ की तुलना में ₹4.50 लाख करोड़ अर्थात 67.99% था।

2. सीपीएसईज़ का संचालन:

(i) व्यय विभाग के निम्नलिखित अनुदेश/दिशा-निर्देश सूचना और अनुपालन के लिए सीपीएसईज़ को परिचालित किए गए थे।

क) सामान्य बीमा निविदाओं में सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के लिए मानदंड के रूप में निवल मूल्य को हटाना।

ख) विवाद से विश्वास I (एमएसएमई के लिए राहत) योजना का विस्तार।

(ii) डीपीई ने दिनांक 11 दिसंबर, 2023 को विनिवेश के तहत सीपीएसईज़ को परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए बनाए गए नए सीपीएसईज़ और सीपीएसईज़ के ऑटो-मोड में वर्गीकरण पर दिशानिर्देश जारी किए।

(iii) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) में विभिन्न स्तर के बोर्ड स्तर से नीचे के सात पदों के सृजन के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

3. सीपीएसईज़ का समझौता ज्ञापन मूल्यांकन:

(i) 101 सीपीएसईज़ के संबंध में वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप देने के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठकें आयोजित की गईं। इनमें से 11 सीपीएसईज़ को एमओयू प्रक्रिया से छूट दी गई थी और 90 सीपीएसईज़ के संबंध में अंतिम समझौता ज्ञापन ऑनलाइन डैशबोर्ड के माध्यम से जारी किए गए थे। इनमें से 88 सीपीएसईज़ के समझौता ज्ञापनों पर ई-हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

(ii) वर्ष 2022-23 के लिए, 88 समझौता ज्ञापनों में से 13 समझौता ज्ञापनों का मूल्यांकन ऑनलाइन डैशबोर्ड के माध्यम से पूरा हो गया है और शेष प्रगति पर हैं।

4. अंतर-मंत्रालयी बैठकें और सीसीईए/मंत्रिमंडल टिप्पणियां:

(i) डीपीई ने अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए परिचालित निम्नलिखित नोटों/प्रस्तावों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं।

क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की शेयर पूंजी बढ़ाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा परिचालित स्थायी वित्त समिति के लिए मसौदा ज्ञापन।

ख) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की शेयर पूंजी बढ़ाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा परिचालित स्थायी वित्त ज्ञापन का मसौदा।

(ii) माह के दौरान डीपीई द्वारा 5 आईएमजी/सीएमसीडीसी बैठकों में भाग लिया गया।

(iii) डीपीई ने आर्थिक कार्य की मंत्रिमंडलीय समिति के लिए मसौदा नोट पर अपनी टिप्पणी प्रदान की, जिसमें निवेश या इक्विटी भागीदारी के माध्यम से विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (केएबीआईएल) के बोर्ड को 500 करोड़ रुपये तक की वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(iv) डीपीई ने आर्थिक कार्य की मंत्रिमंडलीय समिति के लिए मसौदा नोट पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कीं, जिसमें नवरत्न सीपीएसईज़ के लिए लागू उच्चतम सीमा से आगे तलचर फर्टिलाइजर लिमिटेड (टीएफएल) में आरसीएफ द्वारा अतिरिक्त इक्विटी निवेश के लिए अनुमोदन मांगा गया है।

5. सीपीएसईज़ द्वारा एमएसईज़ और जीईएम के माध्यम से खरीद:

(i) वर्ष 2023-24 (दिसंबर, 2023 तक) के दौरान एमएसई से सीपीएसईज़ द्वारा खरीद अनिवार्य 25% (एमएसएमई-संबंध पोर्टल के अनुसार) की तुलना में 35% थी।

(ii) जीईएम के माध्यम से सीपीएसईज़ द्वारा खरीद दिसंबर, 2023 तक 1,57,875 करोड़ रुपये थी, जबकि दिसंबर, 2022 तक यह 56,309 करोड़ रुपये थी।

6. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

(i) सीपीएसईज़ द्वारा किए जाने वाले शीर्ष 30 सीएसआर व्यय ने वर्ष 2023-24 (नवंबर, 2023 तक) के दौरान 1,100 करोड़ रुपये के सीएसआर व्यय की सूचना दी है।

(ii) डीपीई और यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से दिनांक 8 दिसंबर, 2023 को भुवनेश्वर में सीएसआर पर पहली क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला को सभी हितधारकों जिसमें ओडिशा के आकांक्षी जिलों (एडी) के 70 से अधिक प्रतिभागी, सीपीएसईज़, कार्यान्वयन एजेंसियों आदि के सीएसआर नोडल अधिकारी शामिल है से अच्छी प्रतिक्रिया मिली। प्रतिभागियों को चुनिंदा सीपीएसईज़ के साथ ओडिशा के आकांक्षी जिलों के प्रस्तावित मानचित्रण की आवश्यकता के बारे में अवगत किया गया, जिसे अब संबंधित सीपीएसईज़ को उनके इनपुट / फीडबैक के लिए भेजा गया है; साथ ही सीएसआर खर्च को प्राथमिकता वाले विषयों पर निर्देशित करना।

7. क्षमता निर्माण:

डीपीई ने नियोक्ताओं और पेशेवरों के लिए व्यक्तिगत उत्कृष्टता और नई श्रम संहिता के लिए निर्माण दक्षताओं से संबंधित विषयों पर आरडीसी योजना के तहत दिसंबर, 2023 के दौरान 2 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें सीपीएसईज़/एसएलपीईज़ के लिए 76 कार्यपालकों ने भाग लिया।

8. मिशन भर्ती:

अब तक आयोजित रोजगार मेले की 11 श्रृंखलाओं में सीपीएसईज़ की 38,336 नई नियुक्तियों को शामिल किया गया था।

9. एएमआरसीडी मामलों की स्थिति:

अद्यतन स्थिति के अनुसार, पोर्टल पर 145 मामले रिपोर्ट/पंजीकृत किए गए हैं। वित्तीय सलाहकारों के स्तर पर 8 मामलों को रद्द कर दिया गया था। 33 मामले निपटाए गए हैं और 68 मामले निर्णय के लिए सचिवों की समितियों के पास हैं। शेष 36 मामले संबंधित वित्तीय सलाहकारों के पास उनकी संवीक्षा और अनुमोदन के लिए लंबित हैं।

*****